पटना के उच्च न्यायालय में

पूर्ण पीठ

विविध न्यायिक मामला सं. 395/1961

10.08.1961 को निर्णय दिया गया

याचिकाकर्तागणः इन रे: महाबीर प्रसाद

विधिक परिषद् नियम् - नियम 11, 2(1)

याचिकाकर्ता जो अधिवक्ता के रुप में नामांकन के लिये इच्छुक है, उच्च न्यायालय में नियम 11 के तहत नियम 2(1) में छूअ के लिये प्रार्थना किया है जिसमें किसी भी उम्मीदवार को एक साल का प्रशिक्षु होना अनिवार्य बनाया गया है।

अब्दुल, अजीज, विविध न्यायिक मामला सं.-631/1960 जो 9-9-1960(पैट) के फैसले पर भरोसा किया गया।

निर्णित किया गया कि विधिक परिषद् इस नियम से छूट से इन्कार करने में सही थी क्योंकि आवेदक कुछ भी विधि से संबंधित कार्य नहीं कर रहा था।

[पारा 4]

पटना के उच्च न्यायालय में

पूर्ण पीठ

विविध न्यायिक मामला सं. 395/1961

10.08.1961 को निर्णय दिया गया

याचिकाकर्तागणः **इन रे: महाबीर प्रसाद**

माननीय न्यायाधीश/कोरमः (समक्ष)

एस.सी. मिश्रा, एच.के. चौधरी और के. दयाल, न्यायमूर्तिगण

सलाहकारः

बार काउंसिल के लिएः रमाकांत वर्मा, अधिवक्ता

आदेश

1. यह बिहार विधानमंडल पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष श्री महाबीर प्रसाद सिंह द्वारा इस न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए एक आवेदन है। उन्होंने अपने आवेदन में आगे प्रार्थना की है कि उन्हें विविध परिषद् द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 2 (1) से छूट सकता है, जिसमें उन शर्तों को निर्धारित किया गया है जिनके तहत किसी व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया जाना है। उस नियम के लिए आवेदक को इस न्यायालय की सूची पर एक अधिवक्ता के कक्षों में एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसका नाम बार काउंसिल द्वारा तैयार की गई और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित सूची में दिखाई देता है या उसने इंग्लैंड में एक बैरिस्टर के साथ कक्षों में पढ़ा है, जिसका नाम उस न्यायालय की सराय द्वारा अनुमोदित है जिससे आवेदक संबंधित है और उसने ऐसे अधिवक्ता या बैरिस्टर से आवश्यक कानून की डिग्री की आवश्यकता के अलावा प्रशिक्षण और अर्जित दक्षता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

हालांकि, नियम 11 के तहत, यह निर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय विशेष मामलों में बार काउंसिल से परामर्श करने के बाद किसी भी उम्मीदवार को अधिनियम की धारा 9 और 15 के तहत बनाए गए नियमों की सभी या किसी भी आवश्यकता से छूट दे सकता है, और ऐसी छूट दिए जाने पर, उक्त उम्मीदवार को नियमों का पालन किया हुआ माना जाएगा। आवेदक ने पैराग्राफ 7 में कहा है। उनके आवेदन के अनुसार कि वे 1930 में बिहार विधानमंडल पुस्तकालय के लाइब्रेरियन के रूप में सेवा में शामिल हुए और तब से विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों और नियमों, निर्णयों और बहसों के संदर्भों का पता लगाने में लगे हुए हैं, और सामान्य रूप से, संविधान और कानून पर पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। हालाँकि वे 1930 में सेवा में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने 1945 में कानून की डिग्री प्राप्त की। ये आवेदक द्वारा दी गई छूट और ऊपर निर्दिष्ट प्रपत्र में कानून के साथ उसकी परिचितता के आधार हैं।

2. बार काउंसिल ने आवेदन में दिए गए आधारों पर विचार करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि लाइब्रेरियन के रूप में आवेदक की नियुक्ति केवल विधेयकों, अधिनियमों आदि के संदर्भों का पता लगाने के रूप में है, यहां तक कि संविधान और कानून पर पुस्तकों के सामान्य अध्ययन का उनका बयान भी छूट देने के लिए शायद ही पर्याप्त आधार होगा। एक वर्ष की अवधि के लिए एक अधिवक्ता या बैरिस्टर के कक्ष में पढ़ने के लिए एक आवेदक पर जोर देने वाले नियम का कारण मुख्य रूप से उसे इस न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में नामांकित करने से पहले प्रक्रियात्मक कानून से परिचित कराना है। एक व्यक्ति, जो केवल विधेयकों, अधिनियमों, आदि के संदर्भ का पता लगाता है, उसे एक ऐसा व्यक्ति नहीं माना जा सकता है जिसने न्यायालय की प्रक्रिया से परिचित होने के लिए कुछ भी किया है, या यहां तक कि अतीत में उसे कानून का अध्ययन करने और कानून के कुछ प्रावधानों या न्यायालय के फैसलों की कुछ तथ्यों और परिस्थितियों पर प्रयोज्यता पर निर्णय लेने के लिए अपने दिमाग को लागू करने के अवसर भी मिले हैं।

3. नतीजतन, यह नहीं माना जा सकता है कि बिहार विधानमंडल पुस्तकालय के लाइब्रेरियन के रूप में आवेदक कुछ ऐसा कर रहा था जो उसे बार काउंसिल द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 2 (1) के संचालन से छूट का हकदार बना सकता है। बार काउंसिल ने छूट की सिफारिश नहीं की है, इसे नियम 2 (1) के संचालन से आवेदक को छूट देने का निर्णय लेने के लिए हमें भेजा गया है।

4. ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने अपना दृष्टिकोण हमारे सामने नहीं रखा है। हालाँकि, श्री रमाकांत वर्मा बार काउंसिल की राय के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि आवेदक को छूट नहीं दी जा सकती है। उन्होंने विविध न्यायिक मामला संख्या 895/1956 में उल्लिखित कारणों का उल्लेख किया है। .श्री बद्रिका नाथ सरन (पट) के नामांकन के लिए आवेदन के मामले में। उन्होंने आग्रह किया है कि उस संदर्भ की सुनवाई करने वाली पीठ द्वारा अनुमोदित छूट का आधार यह है कि यदि आवेदक का कानून और कानून के न्यायालयों के साथ लंबा संपर्क रहा है, तो उसे नियम 2 (1) के संचालन से अलग किया जा सकता है, और आवेदक को बार काउंसिल द्वारा अनुमोदित अधिवक्ता के कक्षों में एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण की अवधि से गुजरने के बिना एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया जा सकता है।

हमारी राय में, यद्यपि ऊपर निर्दिष्ट निर्णय विशेष रूप से उन परिस्थितियों को सीमित नहीं करता है जिनमें छूट दी जा सकती है, यह अच्छी तरह से हो सकता है कि कानून और कानूनी अदालतों के साथ लंबे संपर्क के अलावा, यदि नियम 2 (1) के संचालन से छूट के लिए एक उपयुक्त मामला बनाया जाता है, तो वह हो सकता है। दिया जाये। लेकिन इस मामले के संदर्भ में हमें यह तय करना होगा कि क्या आवेदक द्वारा इस तरह की छूट के लिए पर्याप्त आधार तैयार किया गया है। हमारी राय में, विविध परिषद् इस नियम से छूट से इनकार करने में सही थी क्योंकि आवेदक जो कर रहा था वह किसी अधिनियम या किसी

विधायी प्रावधान की सामग्री की आलोचनात्मक जांच के लिए अपने दिमाग को लागू करने के बराबर नहीं है या उस मामले के तथ्यों पर विधि न्यायालयों के फैसलों को लागू करने के लिए बहुत कम है। एक लाइब्रेरियन के रूप में अपनी सेवा के दौरान उनका कर्तव्य विधेयकों, अधिनियमों आदि के संदर्भों का पता लगाना और विधानमंडल में निर्णयों और बहस का पता लगाना था, लेकिन कानून के किसी विशेष प्रावधान या मामले के तथ्यों पर निर्णयों की प्रयोज्यता पर विचार करने के लिए अपने दिमाग को लागू नहीं करना था।

इस मामले में, अब्दुल अज़ीज़, एक वकील के रूप में नामांकन के लिए एक आवेदन के मामले में, विविध न्यायिक मामला संख्या 631/1960, डी/- 9-9-1960 (पैट), इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि अनुरोध के अनुसार छूट नहीं दी जा सकती है, हालांकि उन्होंने इस आधार पर छूट का दावा किया था कि उन्होंने इस न्यायालय के अनुवादक के रूप में नियुक्त होने से पहले कुछ समय के लिए एक वकील के रूप में वकालत की थी, और यहां तक कि बाद की क्षमता में भी वे कानून के मामले से निपट रहे थे। छूट के लिए प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार यह था कि एक अनुवादक के रूप में उन्होंने जो कर्तव्य निभाया, उसमें किसी मामले के तथ्यों पर कानून का प्रयोग शामिल नहीं था। हमारी राय में, वर्तमान आवेदक के कर्तव्य लगभग इस न्यायालय के अनुवादक के कर्तव्यों के बराबर हैं, और हमारी राय में, बार काउंसिल ने बार काउंसिल द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 2 (1) के संचालन से छूट के लिए उनकी प्रार्थना को अस्वीकार करने में उचित ठहरायाा गया ।

यदि आवेदक छूट के लिए अपना मामला रखने के लिए प्रति पुत्र या एक अधिवक्ता के माध्यम से यहां उपस्थित था, तो हम इस बात पर विचार करने के लिए इच्छुक होंगे कि क्या इस न्यायालय में आवेदक द्वारा उसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण की अवधि को कम किया जाए। इस तरह के अनुरोध के अभाव में, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि

आवेदक को इस न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने से पहले नियम 2 (1) की आवश्यकता को पूरा करना होगा।

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।